एक केस कालकाजी का आया जिसमें कहा गया कि एक और थाना बनाना चाहिये क्योंकि यहां पर ज्यादा केसेज़, ज्यादा अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। कहा गया कि जब तक 75 घटनाएं नहीं हो जाएंगी तब तक पुलिस स्टेशन की स्थापना नहीं की जाएगी। इस तरह से क्या कोई पुलिस स्टेशन की स्थापना करने के लिए 75 केसेज़ का इंतज़ार करेगा? दूसरी एक बड़ी चीज़ मैं कहना चाहती हूं कि महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना के साथ महिलाओं के रेप केसेज़ की जो एफ०आई०आर० लिखी जाए, उस समय वहां उस घटना का वर्णन नहीं करना चाहिये। सिर्फ एक फारमेट होना चाहिए एफ०आई०आर० का और उस फारमेट को भरा जाए। इसके अलावा कोई भी एक संशोधन किया जा सकता है, संविधान संशोधन, कि जिस महिला के साथ रेप केस हो तो उसके कोई रिश्तेदार, भाई बहिन या मां बाप कोई भी आकर उस महिला की तरफ से एफ०आई०आर० लिखवा सकते हैं। फिर महिला पुलिस उसके घर जाकर तहकीकात कर सकती है। यह मैं इसमें एड करना चाहूंगी। खास तौर से महिलाओं के केसेज में एक डाक्टर भी बैठाया जा सकता है और एक साइक्लाजिस्ट भी ताकि महिलाओं की डाक्टरी जांच वहीं की वहीं की जा सकें। मैं इस सदन से अपील करना चाहूंगी कि इस तरह के रिफार्म्स जल्दी से जल्दी लाए जाएं। संविधान संशोधन किया जाए। हम सब तरफ से सुनते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। लेकिन इन अत्याचारों के खिलाफ न्याय दिलाने की पहली सीढ़ी पुलिस स्टेशन है। उनको जब तक हम नहीं सुधारेंगे महिलाओं को न्याय का वादा हम नहीं कर सकते। धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं अपने को इससे एसोसिएट करना चाहती हूं।

Need to make provision of adequate funds for improvement and upgradation of state roads in Orissa

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, Orissa is lagging behind several States in the development of the road sector. Proposals for improvement and upgradation of some important roads in the State of Orissa have not been accepted by the Central Government and are pending acceptance and provision of funds for the last 15 years.

The Government of Orissa has submitted to the Central Government a list of projects for Central assistance and also requested it to propose them for external assistance.

Some of the main projects in the road sector are: (1) Improvement of Bhubaneswar-Puri Road; (2) Improvement of the road from Pipili to Konark; (3) Improvement of the road from Berhampur to Phulbani (4) Upgradation of the Orissa Trunk Road from Balasore to Kharagpur as a national highway; (5) Khurda-Nayagarh-Danapalla Raod; and (6) Cuttack-Chandbali Raod.

The State Government has submitted detailed proposals for all these projects indicating the length, approximate cost and the sources from which funds may be made available for implementing them. The proposals submitted by the State Government are pending since a long time. The development of the State would not be possible without infrastructural development like roads and communications.

I, therefore, urge upon the Government of India to consider these proposals on a priority basis. As a number of projects in various sectors such as steel, industry, transport are coming up in the State, upgradation and improvement of these road projects are very necessary. I appeal to the Government of India to make provision of adequate funds for completion of these projects in the 1996-97 financial year.

Thank you, Sir.

Proposal for modernisation of IISCO, Burnpur

श्री गया सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक उद्योग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पिछले पांच साल में जो सरकार थी उसने कहा कि हम नया औद्योगीकरण और उदारीकरण कर रहे हैं। इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल जी ने जब एच०ई०सी० की नींव दी थी तो उस समय यह घोषणा की थी कि यह हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन हिंदुस्तान में भी नये कारखाने आएंगे उनके निर्माण की मशीनरी वहां तैयार करेगा। आज उसकी ऐसी हालत है कि वह सिक है। वहां के मजदूरों ने उसका